डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2015-17

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

# मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 61 ● अंक 03 ● भोपाल ● 1-15 जुलाई, 2017 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/– ● आजीवन शुल्क 1500/–

## अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस : 1 जुलाई, 2017

## सहकारी संकल्प : कोई न पीछे छूटे

**''कोई न पीछे छूटे''** यह संकल्प है – इस बार के 95 वें अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस का। यह दिवस प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। इसका निर्धारण अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी परिसंघ द्वारा किया जाता है। सहकारिता को एक सूत्र में बांधने की दृष्टि से 1895 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी परिसंघ की स्थापना की गई। संघ ने सहकारिता विश्व को एक ऐसा मंच प्रदान किया, जहां से सहकारिता की आवाज सम्पूर्ण विश्व में गुंजायमान हो सके। परिसंघ ने सहकारिता को विश्व स्तर पर एकत्र करने का कार्य प्रारंभ किया। कालांतर में इस संघ को ऐसा प्रतीत हुआ कि विश्व स्तर पर विशिष्ट दिवस सहकारिता के पहचान के रूप में मनाया जाना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर 1922 में इसके कार्य संचालन समिति में तत्कालीन अध्यक्ष श्री जी.जे.डी.सी. गोदर्थ ने यह प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार करते हुए यह निश्चित किया गया कि जुलाई माह का प्रथम शनिवार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में आयोजित किया जाये।

**सर्वप्रथम 1923 में जुलाई माह के प्रथम शनिवार को इस दिवस का शुभारंभ हुआ,** जिसमें सहकारिता संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय एकता, आर्थिक दक्षता, शांति और समानता पर चर्चा की गई थी, तभी से यह दिवस उल्लासपूर्वक मनाया जा रहा है। इसमें विशेष बात यह हुई कि वर्ष 1995 में जब इस परिसंघ का शताब्दी महोत्सव आयोजित हुआ इसमें पुनः एक बार सहकारिता के सिद्धान्तों को युक्तियुक्त करते हुए नीवन सिद्धांतों को स्थापित किया गया एवं इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्रदान कर सहकारी विश्व को गौरवांवित किया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी परिसंघ प्रत्येक वर्ष इस दिवस के लिए केन्द्रीय विचार बनाकर मनाने के लिए प्रेरित करता आ रहा हैं, सामान्य रूप से आंदोलन की प्रगति एवं भविष्य की योजनाओं पर तो विचार किया ही जाता, विशिष्ट विचार बिन्दु पर अधिक सार्थक चर्चा होती है।

स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह दिवस क्यों और कैसे, किसलिए मनाया जाता है। इन प्रश्नों के उत्तर देखने के पूर्व यह समझना आवश्यक है कि सहकारिता का इतिहास क्या है। सहकारिता का विकास कब और कैसे हुआ, यह कहना कठिन है, किंतु यह निश्चित है कि मानव ने किसी अन्य व्यक्ति के सहयोग एवं सहायता की अपेक्षा जब की होगी, उसी समय इसका बीजा रोपण हुआ होगा। उक्त आधार पर सहकारिता का क्रमिक इतिहास तीन क्रम में बांधा जा सकता है – प्राचीन सभ्यता काल, मध्ययुग, आधुनिक काल। ईसा के तीन हजार वर्ष पूर्व मिस्त्र सामाज्य में फराओं के काल में दस्तकारों ने सहकारी संघों की स्थापना की थी। प्राचीन बेबीलोनिया की कृषि व्यवस्था सहकारिता पर ही आधारित थी। इसी प्रकार प्राचीन यूनान की सभ्यता सहयोग और सहकारिता पर ही आधारित थी। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि मनुष्य के दाह संस्कार के लिए भी

शेष पृष्ठ 6 पर

## मुख्यमंत्री ने रतलाम जिले की बड़ावदा सहकारी संस्था का किया आकस्मिक निरीक्षण

### उपार्जन, भुगतान और ऋण वितरण की समीक्षा

**भोपाल।** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जावरा से उज्जैन जाते हुए मार्ग में सेवा सहकारी समिति मर्यादित बड़ावदा का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने समिति के कार्यो की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने समर्थन मूल्य में उपार्जित किये गये गेहूँ के भुगतान की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को एक साथ खरीफ एवं रबी की फसलों के लिये दिये जाने वाले ऋण के लिये राशि की व्यवस्था संबंधी समीक्षा भी की।

श्री चौहान ने विगत वर्ष में किसानों की फसलों को हुए नुकसान के उपरांत सरकार द्वारा अल्पकालीन ऋण को मध्यकालीन में बदलने के लिये किसानों के द्वारा तीन किश्तों में जमा राशि और जमा कराने से शेष रहे किसानों की जानकारी भी ली। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष श्री अशोक चौटाला ने समिति द्वारा किये गये कार्यो से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

## किसानों से प्याज खरीदी का समय पर भुगतान करवाएँ

### सहकारिता राज्य मंत्री ( स्वतंत्र प्रभार ) द्वारा प्याज खरीदी की समीक्षा

**भोपाल।** सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने राज्य सरकार द्वारा किसानों से 8 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज खरीदी की समीक्षा की। मंत्रालय में हुई बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य श्री के. सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी और एम.डी. मार्कफेड श्री ज्ञानेश्वर पाटिल मौजूद थे।

राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि किसानों से प्याज खरीदी के साथ खरीदी गई प्याज को उपभोक्ताओं को देने की माकूल व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा खरीदी केन्द्र पर दी गई प्याज का भुगतान उन्हें समय पर करवायें। प्याज बिक्री में किसानों को किसी तरह की दिक्कत न हो। प्रदेश में अब तक 67 प्याज खरीदी केन्द्रों पर 13 लाख 965 क्विंटल प्याज 26 हजार 919 किसानों से खरीदी गई है।

# प्रदेश में एक दिन में लगेंगे 6 करोड़ से अधिक पेड़

## पर्यावरण के संरक्षण के महाअभियान में समाज के हर वर्ग की भागीदारी हो- मुख्यमंत्री श्री चौहान

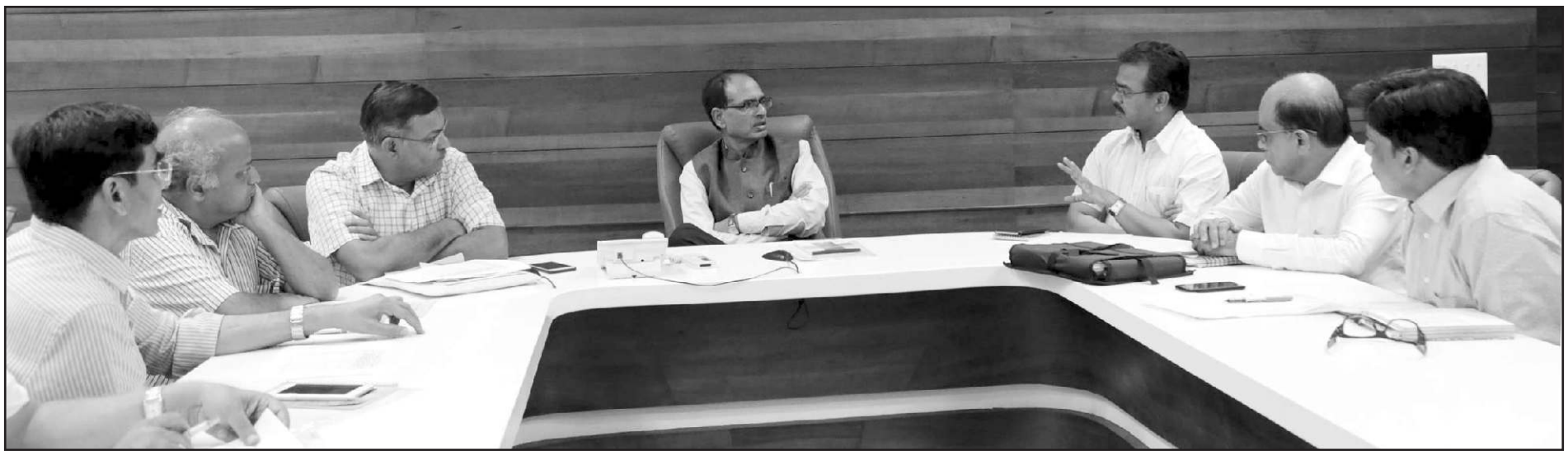

**भोपाल।** प्रदेश में एक दिन में आगामी 2 जुलाई को 6करोड़ से अधिक पेड़ लगाने की व्यापक तैयारियां जारी हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां मंत्रालय में इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के इस महाअभियान में समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाये। जिलावार तैयारियों की सघन मॉनीटरिंग की जाये। बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा तट के सभी चौबीस जिलों की कार्य योजना बनायी जाये। पौधों की उपलब्धता तथा पौधों के परिवहन के लिये रुट चार्ट बनायें जाये। इस कार्य से जुड़े प्रत्येक विभाग से प्रतिदिन प्रगति की जानकारी ली जाये। पौधे लगाने में समाज के सभी वर्गों के जनप्रतिनिधियों, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों, शासकीय कर्मियों, अशासकीय संगठनों की भागीदारी रहे। प्रत्येक जिले में किस स्थान पर और कौन पौधे लगायेंगे तथा वे उस स्थल तक कैसे पहुंचेंगे इसकी कार्ययोजना बनायें। कृषि, उद्यानिकी, वन सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी क्षेत्र में जाकर तैयारियां करायें।

बैठक में बताया गया कि अब तक जिलों में पौधे लगाने के लिये करीब 4 करोड़ 80 लाख गड्डे तैयार कर लिये गये हैं तथा शेष गड्डे शीघ्र तैयार कर लिये जायेंगे। सभी जिलों में पौधों की व्यवस्था कर ली गयी है। जिलों में करीब ढाई लाख वृक्ष सेवकों का पंजीयन हो चुका है तथा पंजीयन कार्य अभी जारी है। बैठक में अपर मुख्य सचिव वन श्री दीपक खांडेकर, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री आर.एस. जुलानिया, प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव द्वय श्री अशोक वर्णवाल और श्री एस.के. मिश्रा और प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अनिमेष शुक्ला उपस्थित थे।

# मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग गठित

**भोपाल।** प्रदेश में कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन की बेहतर सुविधाओं संबंधी अनुशंसा करने के लिये मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग का गठन किया गया है। आयोग का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। कृषि कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा आयोग के लिये यथा अपेक्षित प्रशासकीय अमला और बजट उपलब्ध करवाया जायेगा। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को वेतन भत्ते तथा अन्य सुविधाएँ देने के संबंध में अलग से आदेश जारी किये जायेंगे।

राज्य शासन द्वारा इस संबंध में जारी आदेशानुसार कृषि के क्षेत्र में अनुभवी व्यक्ति को इस आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया जायेगा। दो कृषक सदस्य शासन द्वारा मनोनीत किये जायेंगे, जो कृषि कार्य एवं कृषि विपणन के क्षेत्र में अनुभवी होंगे। साथ ही दो कृषि अर्थशास्त्रियों का आयोग में मनोनयन किया जायेगा। शासकीय प्रतिनिधि के रूप में पदेन कृषि उत्पादन आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग आयोग में सदस्य रहेंगे। पदेन संचालक किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग आयोग के सचिव होंगे।

यह आयोग खरीफ, रबी तथा ग्रीष्मकालीन फसलों की लागत की गणना कर राज्य शासन को अनुशंसा करेगा। राज्य सरकार द्वारा बाजार हस्तक्षेप योजना में अपेक्षा किये जाने पर चयनित जिन्स की बाजार हस्तक्षेप दर के लिये राज्य शासन को सुझाव भी देगा। कृषि विपणन क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिये सुझाव देने के साथ-साथ शासन के निर्देशानुसार समय-समय पर विभिन्न फसलों के लिये अध्ययन करेगा। इसी के साथ, आयोग शासन को आवश्यकतानुसार कृषि मूल्य संबंधी एवं अन्य उत्पादन संबंधी समस्याओं पर सलाह भी देगा। इसके अलावा आयोग राज्य शासन द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य भी करेगा।

आयोग खरीफ, रबी एवं ग्रीष्मकालीन फसलों की अवधि से पहले प्रतिवर्ष राज्य शासन को तीन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। आयोग की संचालन प्रक्रियाएँ तथा आपरेशनल गाईडलाइन आयोग द्वारा अनुशंसित किये जाने पर राज्य शासन द्वारा पृथक से जारी की जायेंगी। आयोग में अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिये भी अलग से आदेश जारी किये जायेंगे।

### 75 करोड़ की राशि से मछुआ सहायता कोष बनेगा

**भोपाल।** मध्यप्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड की प्रथम बैठक आज डॉ. कैलाश विनय की अध्यक्षता में हुई। बैठक में राज्य स्तर पर 75 करोड़ रुपये का मछुआ सहायता कोष बनाने, जिला स्तर पर आदर्श मछुआ समिति बनाने, छानबीन समिति के स्वरूप में बदलाव और जिला स्तर पर मत्स्य-मित्र तैयार करने जैसे अनेक सुझाव पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त मछुआरा होने के प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव तथा सिंघाड़ा खेती को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई। बैठक में बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री सीताराम बाथम, श्री राजू बाथम, संचालक मत्स्य उद्योग श्री ओ.पी. सक्सेना तथा बोर्ड सदस्य उपस्थित थे।

### डिजी गाँव परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बनी समिति

**भोपाल।** राज्य शासन द्वारा डिजी गाँव परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति के अध्यक्ष होंगे।

समिति में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिनिधि, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रतिनिधि, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रतिनिधि और स्कूल शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी मैन-आईटी सदस्य सचिव होंगे।


**पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-**
**डी.सी.ए. मात्र 8100/-**
**न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए. स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)**

**प्रवेश प्रारंभ**

**मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित**
**सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल**
(माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)
ई-8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड-462 039
फोन.-0755 2725518, 2726160 फेक्स-0755 2726160
Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com

# प्याज की खरीदी तिथि 15 जुलाई और मूंग, उड़द की खरीदी 31 जुलाई करने का आग्रह

## मुख्यमंत्री श्री चौहान की केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री सिंह से मुलाकात

**भोपाल।** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह से मुलाकात कर मध्यप्रदेश में प्याज के बम्पर उत्पादन से उत्पन्न स्थिति से अवगत करवाया। श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में प्याज का उत्पादन 32 लाख मीट्रिक टन संभावित है। बम्पर उत्पादन के साथ उत्पादन की गिरती कीमतें चिन्ता का विषय है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक 3 लाख 92 हजार मीट्रिक टन प्याज की खरीदी कर ली है। भारत सरकार ने प्याज खरीदने के लिए 30 जून तक की तिथि निर्धारित की है। प्याज की बढ़ती आवक को देखते हुए श्री चैहान ने अनुरोध किया कि प्याज की खरीदी की तिथि 15 जुलाई तक बढ़ाई जाय जिससे किसानों द्वारा लाई जा रही प्याज को खरीदा जा सके और किसानों को उचित मूल्य मिल सके। श्री चौहान ने कहा कि एम.आई.एस. के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 2 लाख मीट्रिक टन के निर्धारित लक्ष्य को बढ़ाकर 8लाख मीट्रिक टन किया जाय।

श्री चौहान ने ग्रीष्मकालीन फसल जैसे मूंग, उड़द और अरहर के लिए समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत क्रय संबंधी विषयों पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी तक प्रदेश में मूंग की कुल खरीदी 24 हजार 115 मीट्रिक टन और 4,350 मीट्रिक टन उड़द की खरीदी हो चुकी है। बम्पर उत्पादन को देखते हुए श्री चौहान ने आग्रह किया कि भारत सरकार द्वारा बाजार में हस्तक्षेप कर मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से 31 जुलाई तक मूंग और उड़द की खरीदी की जाये। इसी प्रकार, मध्यप्रदेश अरहर (तुअर) का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है। अभी तक मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश में 1.02 लाख मीट्रिक टन अरहर की खरीदी की गई है। भारत सरकार द्वारा मई-जून में अनुमति नहीं होने से राज्य सरकार ने 10 जून से अपने स्त्रोतों से 5960 मीट्रिक टन अरहर की खरीदी की है।

# जैविक खेती अपनाकर अधिक मुनाफा कमा रहे समूह सदस्य

## कृषि आधारित गतिविधियों से 11 लाख 30 हजार ग्रामीण निर्धन परिवार जुड़े

**भोपाल।** स्व-सहायता समूह सदस्यों को कम लागत में अधिक मुनाफा दिलाने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षित 4200 से अधिक स्व-सहायता समूह सदस्यों को उन्नत बीज, कीट उपचार, जैविक खाद उत्पादन एवं उपयोग, फसलों में नवाचार तथा आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रदेश में लगभग 11 लाख 30 हजार से अधिक ग्रामीण निर्धन परिवारों को आजीविका मिशन द्वारा कृषि आधारित गतिविधियों से जोड़ा जा चुका है।

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में समूह सदस्यों द्वारा 5,10,520 वर्मी पिट/नाडेप बनाये गये हैं। एक पिट से 2.5-2.7 टन जैविक खाद निकलती है जो एक एकड़ खेती के लिए पर्याप्त होती है। इस खाद का उपयोग बढने से रासायनिक खाद के उपयोग में कमी आई है। उन्नत बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत 37 बीज उत्पादन समितियां पंजीकृत करवाई गई हैं जिनके माध्यम से उचित गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन कर स्व-सहायता समूह सदस्यों को उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में एक लाख से अधिक कृषक प्रमाणित बीज का उपयोग कर रहे हैं।

महिला किसान सशक्तिकरण के लिए 35 हजार 116महिला किसानों को लाभान्वित किया गया है। चौबीस उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया है जिनमें 20 कृषि आधारित, 02 दुग्ध, 02 मुर्गीपालन से संबंधित हैं। पोषण वाटिका में उगाई जाने वाली सब्जियों के बीज अब हॉर्टीकल्चर विभाग द्वारा बांटे जायेंगे। समूह सदस्यों द्वारा जैविक सब्जी का विपणन 297 आजीविका फ्रेश दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है।

बड़वानी, शहडोल एवं सागर जिले में हल्दी, अलीराजपुर में सफेद मूसली, धार में आलू, बड़वानी में मिर्च, नरसिंहपुर में दलहन, मंडला में धान, गुना में धनिया और श्योपुर में कद्दू के उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया है।

विदिशा जिले में ड्रिप मल्चिंग को बढ़ाने में सहयोग किया गया है। व्यवसायिक सब्जी आदि सहित अन्य फसलों के उत्पादन में प्रोत्साहन एवं सहयोग के लिए सी.आर.पी. द्वारा प्रतिदिन मानदेय के आधार पर काम किया जा रहा है। मध्यप्रदेश की कृषि सी.आर.पी. द्वारा हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में भी काम किया जा चुका है।

## अधिक कृषि उत्पादन और समग्र विकास के लिए मध्यप्रदेश पुरस्कृत

**भोपाल।** मध्यप्रदेश को कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक उत्पादन और प्रदेश में कृषि के समग्र विकास के लिए दो पुरस्कार से नवाजा गया। नई दिल्ली के पूसा में आयोजित कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने प्रदेश के कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पूसा में एग्रो समिट 2017 **क्या हम वाकई में किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर सकते हैं** पर परिचर्चा भी हुई। परिचर्चा में कृषि विशेषज्ञों, कृषि वैज्ञानिकों आदि ने अपने विचार रखे।

कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने पुरस्कार ग्रहण करने के बाद कहा कि पिछले चार साल से मध्यप्रदेश की कृषि विकास दर 20 प्रतिशत से अधिक है। श्री बिसेन ने इसका श्रेय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व, उनकी योजनाओं, किसानों की मेहनत और कृषि वैज्ञानिकों को दिया।

## पीडीएस उपभोक्ताओं को राशन के साथ प्याज लेना बाध्यता नहीं- मंत्री श्री धुर्वे

**भोपाल।** खाद्य, नागरिक आपूर्ति-उपभोक्ता संरक्षण राज्य मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे ने कहा है कि पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को राशन के साथ प्याज लेना बाध्यता नहीं है। इस संबंध में यदि कोई ऐसा कहता है वह गलत है। शासन द्वारा राशन के साथ अनिवार्य रूप से प्याज लेने का कोई आदेश नहीं दिया गया है।

श्री धुर्वे ने बातया कि किसानों से खरीदी गई प्याज को नाममात्र की कीमत 2 रूपये प्रति किलो के मान से पीडीएस दुकान के माध्यम से राशन प्राप्त करने वाले परिवारों को उपलब्ध करवाई गई हैं। राशन लेने वाले परिवार की इच्छा पर निर्भर है कि वह अपनी सुविधानुसार प्याज ले अथवा नहीं ले। राशन के साथ प्याज लेना कतई बाध्यकारी नहीं है।

# मार्कफेड द्वारा खरीदी गई प्याज का अन्य जिलों को परिवहन जारी
## समर्थन मूल्य पर अब तक खरीदी गई 1.30 लाख क्विंटल प्याज

**भोपाल।** मार्कफेड भोपाल द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही प्याज का प्रदेश के ऐसे जिलों में परिवहन आरंभ कर दिया गया है जहां प्याज की कमी है। मार्कफेड द्वारा भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा के साथ साथ हरदा से भी प्याज की खरीदी की जा रही है। अभी तक 13011 क्विंटल प्याज की खरीदी 8रूपये प्रति किलो समर्थन मूल्य के मान से खरीदी गई है तथा 53275 क्विंटल प्याज मंडल, कटनी, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, शहडोल, मुरैना, भिण्ड, दतिया, छतरपुर और बैतूल जिलों को भेजने की व्यवस्था की गई है। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भी जरूरतमंदों को प्याज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

सहकारी विपणन संघ के मंडल प्रबंधक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार खरीदी गई प्याज का विभिन्न जिलों को भंडारण व विक्रय हेतु परिवहन भी किया जा रहा है। भोपाल जिले से खरीदी गई प्याज का परिवहन मंडला व कटनी जिलों को किया गया है। अब तक मंडला जिले को 6402.76 क्विंटल तथा कटनी जिले को 15870.60 क्विंटल प्याज भेजी जा चुकी है ।इसी तरह सीहोर जिले से 11024 क्विंटल प्याज होशंगाबाद को क्विंटल, 749 क्विंटल प्याज नरसिंहपुर जिले को तथा 9144 क्विंटल प्याज शहडोल भेजी जा चुकी है। इसके अलावा रायसेन में क्रय की गई प्याज में से 390.50 क्विंटल नरसिंहपुर भेजी गई है जबकि विदिशा जिले से 610 क्विंटल प्याज मुरैना भेजी गई है। राजगढ़ जिले के विभिन्न केन्द्रों पर खरीदी गई प्याज में से 1536.80 क्विंटल प्याज दमोह, 1564.60 क्विंटल भिण्ड, 1214.65 क्विंटल दतिया, 2090 क्विंटल छतरपुर और 1155.40 क्विंटल प्याज शहडोल भेजी जा चुकी है। इसी तरह हरदा में खरीदी गई प्याज में से 1139.10 क्विंटल प्याज बैतूल भेजी जा चुकी है। मंडल प्रबंधक सहकारी विपणन संघ द्वारा बताया गया कि संभाग में बनाये गये 13 खरीद केन्द्रों में से भोपाल जिले में करोंद मंडी व बैरसिया में खरीद केन्द्र स्थापित किये गये हैं जबकि सीहोर जिले में सीहोर, इछावर व आष्टा में, विदिशा जिले के गंज बासोदा, रायसेन जिला मुख्यालय, राजगढ़ जिले के ब्यावरा, सारंगपुर, नरसिंहगढ़, जीरापुर व खुजनेर तथा हरदा जिला मुख्यालय पर प्याज खरीद केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

# जिला सहकारी संघ की आमसभा सम्पन्न

उज्जैन। जिला सहकारी संघ की 56 वीं वार्षिक आमसभा उपायुक्त सहकारिता एवं प्रभारी अधिकारी डा. मनोज जायसवाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। आमसभा में संघ का वर्ष 2016–17 का वार्षिक प्रतिवेदन, अंकेक्षित वार्षिक पत्रक, अंकेक्षक की नियुक्ति एवं वर्ष 2017–18 का प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम, अनुमानित वार्षिक बजट की उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा सर्वानुमति से स्वीकृति दी जाकर जिला संघ द्वारा वर्ष में किये गये कार्यक्रमों की प्रशंसा की गई। इस अवसर पर बैठक के अध्यक्ष डा. मनोज जायसवाल ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि जिला संघ अपने सीमित आय एवं साधनों के उपरांत भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति दृढ़ता पूर्वक कर रहा है। जिला संघ उज्जैन के कार्यो को देखते हुवे राज्य संघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन भोपाल में माननीय सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग जी के हाथो श्रेष्ठ पुरूस्कार से स्मृति चिन्ह भेट कर राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। आप सभी की ओर से संघ के कार्य संचालन में प्राप्त परोक्ष, अपरोक्ष सहयोग के लिये जिला संघ आपका आभारी रहेगा तथा भविष्य में इसी प्रकार के सहयोग की अपील करता हूं। बैठक में वर्ष का लेखा–जोखा प्रबंधक जगदीशप्रसाद बैरागी ने प्रस्तुत किया। बैठक में राजपाल सिंह सिसोदिया, योगेन्द्र सिंह (कोकलाखेड़ी) देवेन्द्रसिंह डोडिया, भरतदास बैरागी, रमेश पंडया, रमेश कुमावत, पुरूषोत्तम शर्मा, करणसिंह पटेल, राजेंन्द्र सिंह, भगवानदास गिरी, लक्ष्मणसिंह, बी.एल. बड़गौत्री, भगवानसिंह पवार, भारतसिंह सोलंकी, दिनेश परिहार, गिरधारीलाल नागर, महिपालसिंह चौहान, (एडवोकेट), यशवंत जैन, विनय शाह, सुदेश नीमा, राजेन्द्र लाडुना,गुमानसिंह, दिनेश बैरागी, प्रदीप बदनोरे, विजय शुक्ला, श्रीमती सुनीता कश्यप, अंतिम जैन, रमेश जैन, जितेन्द्रसिंह डोडिया, उदयसिंह दरबार, गजराजसिंह झाला, विजेन्द्र बैरागी, दिलीप नीमा, रमेश आचार्य, डा. विजयकुमार जैन, सी.एस. असोड़िया, विनायक राजुरकर, एन.पी. बोहरे, प्रदीप नाहटा, दिनेश दंदेरिया, हरिशंकर यादव, शिवकुमार गेहलोत आदि उपस्थित थे।

# प्याज के क्रय–विक्रय पर निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित

**भोपाल।** प्रदेश की मंडियों में प्याज की घटती हुई दरों एवं किसानों को हो रही हानि को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा 8रूपये प्रति किलोग्राम की दर से किसानों से प्याज खरीदी जा रही है। प्याज की खरीदी एवं वितरण पर निगरानी रखने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर 0755–2550490 है। नियंत्रण कक्ष सुबह 9 से शाम 7 बजे तक कार्यरत रहेगा।

किसानों को प्याज के विक्रय में कठिनाई आने पर इस दूरभाष पर निराकरण के लिए सम्पर्क किया जा सकता है।

प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूँग, तुअर और उड़द की खरीद लगातार जारी है। इसके अलावा राज्य शासन द्वारा घोषित 8रूपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर किसानों से प्याज भी खरीदी जा रही है।

आज की स्थिति में समर्थन मूल्य पर 302344.03 क्विंटल मूँग, 57051.52 क्विंटल उड़द और 61109 क्विंटल तुअर की खरीदी की जा चुकी है। साथ ही 39 लाख 2 क्विंटल प्याज की खरीदी 8रूपये प्रति किलोग्राम के मूल्य से किसानों से की गई है।

# मनरेगा में श्रेष्ठ कार्यों के लिये मंडला जिला, सीतामऊ ब्लाक और मोरपानी पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार

**भोपाल।** मनरेगा में श्रेष्ठ कार्यों के लिए प्रदेश के मण्डला जिला, मंदसौर जिले के सीतामऊ ब्लाक और होशंगाबाद जिले की केसला जनपद की मोरपानी ग्राम पंचायत को आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरूस्कृत किया गया। वर्ष 2015–16में प्रदेश के मण्डला जिले में मनरेगा में श्रेष्ठ कार्य करने वाले तत्कालीन कलेक्टर श्री लोकेश जाटव, सीतामऊ जनपद की सी.ई.ओ. श्री डी.एस. मसराम एवं मोरपानी ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती संगीता ठाकुर ने पुरस्कार ग्रहण किये।

प्रदेश के मण्डला जिले में वर्ष 2015–16में मनरेगा के तहत 1 लाख 31 हजार से अधिक परिवारों को 54 लाख 24 हजार दिनों का रोजगार दिया गया तथा बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने और वृक्षारोपण के माध्यम से ग्रामीणों को आजीविका के साथ–साथ विकास के विभिन्न कार्य संपादित किये गये। मंदसौर जिले के सीजामऊ में मनरेगा सृजित परिसंपत्तियों को जियो टैगिंग करने का कार्य किया गया तथा मोरपानी ग्राम पंचायत के अंतर्गत काम करने वाले परिवारों को नौ हजार से अधिक दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया गया।

# प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूँग, उड़द और तुअर की खरीद जारी
### शासकीय भूमियों का प्रभावी प्रतिरक्षण होगा

**भोपाल।** मध्यप्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग द्वारा बहुमूल्य शासकीय भूमियों के संदर्भ में राज्य शासन के पक्ष को मजबूत बनाने का दायित्व सौंपा गया है। इसके संबंध में आयोग द्वारा जिला कलेक्टर्स को राजस्व न्यायालय में शासकीय भूमियों से लंबित प्रकरणों की जानकारी मांगी है। इसके अलावा जिला न्यायालय, व्यवहार न्यायालय, राजस्व मंडल, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जानकारी भी विभिन्न प्रारूपों के माध्यम से चाही गई है।

# किसानों की सहूलियत के लिए बनेगी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला

## मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की समीक्षा

**भोपाल।** किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश में 265 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएँ खोली जायेंगी। अभी तक 205 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के अपने भवन बन गए हैं। शेष का निर्माण चल रहा है। प्रदेश में किसानों को 85 लाख 19 हजार मिट्टी परीक्षण कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। लक्ष्य 88लाख 72 हजार मृदा परीक्षण कार्ड वितरित करने का रखा गया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यहाँ मंत्रालय में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की संरचना, अमले की व्यवस्था और संचालन की समीक्षा बैठक में बताया गया कि इन प्रयोगशालाओं में मिट्टी के सूक्ष्म तत्वों की मात्रा की जाँच होगी। इससे किसानों को फसलों का चुनाव करने, उचित मात्रा में खाद देने एवं उपयुक्त बीज लगाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निचले विभागीय अमले को किसानों के साथ लगातार संवाद रखने के निर्देश दिये ताकि उन्हें मार्गदर्शन मिलता रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा सूचित और शिक्षित करने की आवश्यकता है ताकि वे समय से खेती शुरू कर इसे लाभकारी व्यवसाय बनाये।

बैठक में कृषि मंत्री डॉ. गौरीशंकर बिसेन, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री ए.पी. श्रीवास्तव, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीणा, प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री अशोक वर्णवाल, सचिव मुख्यमंत्री श्री विवेक अग्रवाल एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

# प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत मिश्रीलाल बने अपने घर के मालिक

**भोपाल।** उज्जैन जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन तेजी से किया जा रहा है। जिले के कई बेघर निर्धन वर्ग के व्यक्ति इस योजना से अपने घर के मालिक बन गये हैं। उज्जैन के पास ग्राम चिन्तामन जवासिया के मिश्रीलाल वर्मा भी इनमें शामिल है।

झाड़ू निर्माण से अपना गुजर-बसर करने वाले मिश्रीलाल 15 साल पहले चन्द्रावतीगंज से रोजगार के लिये उज्जैन आये थे। तब से वे छोटे से कच्चे घर में अपना बसर कर रहे थे। इनके साथ तीन बच्चे, पत्नी सहित माता-पिता भी एक कमरे के घर में रहते थे। इस वजह से सर्वे सूची में इनका नाम शामिल किया गया। सूची के आधार पर मिश्रीलाल का नाम सर्वोच्च प्राथमिकता वाले नामों में शामिल किया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना में मिश्रीलाल को एक लाख 20 हजार रुपये घर निर्माण के लिये मिले। मिश्रीलाल ने इस राशि में अपने पास जोड़ी गई कुछ पूँजी को मिलाकर चार कमरों वाले घर का निर्माण कर लिया। उनके घर में पक्के लेट-बाथ भी बन गये हैं। चिन्तामन जवासिया ग्राम में 17 आवास पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मंजूर हुए हैं।

**पी डी एस से राशन प्राप्त करने वाले अपना आधार नम्बर दर्ज करायें**

**भोपाल।** पी.डी.एस. से राशन प्राप्त करने वाले सभी हितग्राहियों से अपना आधार नम्बर दर्ज कराने के लिये कहा गया है। ऐसे हितग्राही परिवार जिनकी आधार संख्या पी.डी.एस. का डाटाबेस में दर्ज नहीं है अथवा त्रुटिपूर्ण है, उनको जुलाई 2017 से राशन सामग्री का वितरण अस्थाई रूप से बंद कर दिया जायेगा। खाद्य विभाग द्वारा सभी हितग्राहियों से अनिवार्यत- आधार संख्या दर्ज कराने को कहा गया है। मई 2017 तक 5 करोड़ 35 लाख में से 3 करोड़ 92 लाख हितग्राहियों की आधार संख्या दर्ज की जा चुकी है। दर्ज आधार संख्या का प्रमाणीकरण भी किया जा रहा है।

खाद्य विभाग द्वारा हितग्राहियों से आग्रह किया गया है कि वह अपनी सही आधार संख्या राशन दुकान/ जिला खाद्य कार्यालय/ स्थानीय निकाय में सम्पर्क करवा दर्ज करा सकते हैं।

# प्रदेश में एक लाख 64 हजार से अधिक ग्रेवल सड़के निर्मित

**भोपाल।** मनरेगा योजनान्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बनाई गई ग्रेवल सड़कों से अब पूरे साल लोगों को सुगम यातायात मुहैया करा रही है। दूरस्थ क्षेत्रों के दुर्गम इलाकों में इन ग्रेवल सड़कों पर वाहन दौड़ते नजर आ रहें हैं। ग्रेवल सड़कों के बन जाने से ग्रामीणों का आवागमन सुगम होने के साथ-साथ बरसात के दिनों में बच्चों का स्कूल पहुँचना भी आसान हुआ है।

मध्यप्रदेश में मनरेगा के योजना के अंतर्गत अब-तक गाँवों की आबादी को मुख्य मार्गों तक जोड़ने के लिए तकरीबन 1 लाख 64 हजार 941 सड़कों का काम पूरा कराया जा चुका है तथा वर्तमान में 22 हजार 473 सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनायी गयी परन्तु ये सड़कें न्यूनतम 500 तक की आबादी के हिसाब से बनायी गयी थीं। जिन गांवों-मजरे-टोले की आबादी 500 से कम थी, उन ग्रामों को मुख्य मार्गों तक आने के लिए पगडंडी-नुमा दुर्गम रास्तों से सफर में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। खासकर बरसात के दिनों में जब बच्चों का स्कूल पहुंचना और वाहनों का मुख्य मार्गों तक आवागमन लगभग बंद- सा रहता था। मनरेगा से बनी ग्रेवल सड़कों से ग्रामीणों की यह समस्या समाप्त हो गई है। अब छोटे मजरे-टोले को सुदूर सड़कों के माध्यम से बारहमासी सड़कों तक कनेक्टिविटी मिल जाने से पूरे साल आवागमन सुगम हो गया है।

मनरेगा से बनायी गयी ग्रेवल सड़कों के माध्यम से ग्रामीणों को आवागमन सुविधा का ही नतीजा है कि अब इन गाँवों के बच्चे स्कूल तक पहुँच रहे हैं। ग्रामीणों को खेतों तक पहुंचने के लिए भी ये सड़कें उपयोगी साबित हुयी हैं। किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र को अपने खेतों तक ले जाने में आसानी हो गई है। वाहनों के आवागमन से फसल, सब्जी आदि आसानी बाजार में पहुंचने से उचित दाम मिलने लगा है। इससे ग्रामीणों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है और आमदनी में भी इजाफा हुआ है तथा नगरों के साथ कनेक्टिविटी मिल जाने से ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार आया है। इतना ही नहीं इन सड़कों के निर्माण के दौरान ग्रामीणों को मनरेगा से समुचित रोजगार भी मिला है।

# बजट का बड़ा हिस्सा किसान कल्याण के लिए

## मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नागदा और उन्हेल में किया जन-संवाद

**भोपाल।** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन जिले के नागदा और उन्हेल में जन-संवाद किया। उन्होंने कहा कि नागदा के पास निनाबद में डेम बनाया जायेगा। श्री चौहान ने उन्हेल में महाविद्यालय खोलने और बस स्टेण्ड बनवाने तथा नगर विकास के लिये एक करोड़ रूपये देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट का बड़ा हिस्सा किसान कल्याण के कार्यों में लगाया जायेगा।

श्री चौहान ने कहा कि पैसों के अभाव में कोई भी बच्चा उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। कक्षा 12वीं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी को किसी भी उच्च शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश मिलने पर उसकी फीस सरकार भरेगी। उन्होंने कहा कि सदैव किसानों के हित में कार्य करते रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि किसानों का प्याज 30 जून तक खरीदने के पूरे प्रयास किये जा रहे हैं। इसके बाद भी अगर जरूरत पड़ी तो 30 जून के बाद भी प्याज खरीदी जायेगी। किसानों को उनकी उपज का भुगतान 24 घंटे के अंदर करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों की समस्याएँ सुनी और उनके निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये।

# सोयाबीन कृषकों के लिए उपयोगी सलाह

**भोपाल।** प्रदेश के कई जिलों में हुई मानसून पूर्व वर्षा को देखते हुए किसानों द्वारा सोयाबीन की बोवनी किये जाने के समाचार हैं। जिन किसानों ने सोयाबीन की बोवनी की है, उन्हें नवजात पौधों को बचाने एंव नमी संरक्षण हेतु डोरा कुलपा चलाने की सलाह दी गई हैं। साथ ही कहा गया है कि संभव होने पर सिचांई भी करें। ऐसे क्षेत्र जहां अभी तक सोयाबीन की बोवनी नहीं हुई हैं, वहां के किसानों को सलाह दी गई है कि वे मानसून के आगमन के पश्चात लगभग 100 मिलीमीटर वर्षा होने पर ही सोयाबीन की बोवनी करें।

**प्रथम पृष्ठ का शेष**

# अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस : 1 जुलाई, 2017

सहकारी समितियां थीं, अन्य सहकारी संगठनों में ईंधन और अन्य वस्तुएं एकत्र करके उनके वितरण का कार्य करती थीं।

होन वंश जो ईसा के 200 वर्ष पूर्व चीन में था सर्वप्रथम साख समिति की स्थापना की गई थी। मध्य युग में सामुदायिक जीवन की नई परंपरा जिसे मैनोरियल सिस्टम के नाम से जानते हैं, इसमें सहकारी कृषि की आधारशिला रखी गई। ईसा के मृत्यु प्श्चात दस्तकारों के गिण्डों की स्थापना हुई। इसी दौरान सहकारिता को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में एक समन्वयकारी संस्था माना जाने लगा। पुनर्जागरण काल पंद्रहवीं शताब्दी से लेकर अटारहवीं शताब्दी तक चला, जिसमें वाणिज्यिक क्रांति हुई। सहकारी क्षेत्र में अग्नि बीमा कंपनियां गठित हुई। भूमि बंधक बैंक 1769 में सर्वप्रथम बने। 1750 में औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्थापित किया। यहीं से मानव का शोषण मानव करने लगा। सामाजिक असंतुलन बना शोषित-शोषक जैसी नामावली बनी, तब समाज में जो व्यापक प्रतिक्रिया हुई। इसके फलस्वरूप सहकारिता का जन्म हुआ जो हमें परिचित हैं। औद्योगिक संघर्षो के मध्य सहकारिता के आधार पर ऐसी नींव रखी गई, जिसके अंतर्गत दुर्बल व्यक्ति पारस्परिक सहायता की भावना से संगठित होकर स्वालंबी बन सके। रार्बट ओवेन जो सहकारिता के भीष्म पितामह कहलाते हैं, इन्होंने श्रमिक व्यक्तियों से संबंधित प्रयोग किये। इन्होंने कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया फिर रॉकडेल अग्रगामियों द्वारा उपभोक्ता सहकारिता का श्रीगणेश हुआ। यह कार्यकाल 1844 का था, एचएफ शल्जे डेविश जर्मनी में शहरी साख के प्रणेता बने। फ्रांस में चार्ल्स कूरियर ने समाजवादी समाज की रचना की व्याख्या की। इस प्रकार क्रमशः इटली, भारत, कनाडा, लेटिन अमेरिका, बेल्जियम, नीदरलैंड, अफ्रीका, एशिया, ब्रिटिश में यह सहकारी आंदोलन किसी न किसी रूप में स्थापित होते चला गया। जनता के मध्य जनता का आंदोलन जनता के हित में इसका आदर्श रहा। पूर्वी देशों में सहकारी आंदोलन का सूत्रपात सरकार ने किया। पूर्व सोवियत रूस ने सहकारी आंदोलन को सरकार का अंग बना दिया।

सहकारिता एक जन आंदोलन है। इसमें सभी एक-दूसरे का सहयोग करते है। सभी बराबर होते है। अपनी इच्छा से जुड़ते है। भारत में सहकारिता ने विकास में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया है। आइये आज संकल्प ले **"कोई न पीछे छूटे"** को सहकारिता में सबका साथ सबका विकास को सार्थक करने में अपनी भूमिका स्थापित करें।

## पपीता की उन्नत उत्पादन तकनीकी विषय पर कृषक प्रशिक्षण का आयोजन

**बड़वानी।** कृषि विज्ञान केन्द्र बड़वानी द्वारा ग्राम साकड़ (अंजड़) में पपीता की उन्नत उत्पादन तकनीकी विषय पर कृषक प्रशिक्षण का आयोजन 23 जून को किया गया। प्रशिक्षण के दौरान केन्द्र के उद्यानिकी वैज्ञानिकी डॉ. दिनेश जैन ने प्रशिक्षणार्थियो को फसल विविधीकरण के अंतर्गत पपीता की उन्नत किस्मे अर्का सूर्या, पूसाडेलशियस, कुर्ग हनीड्यू, वाइवान 786की पूर्णत: स्वस्थ पौध खेत में 2ग2 की दूरी पर सितंबर, अक्टूबर के दौरान रोपने की तकनीकी बताई। पौधो को रोपने के पूर्व हाइकोडर्मा एवं नीम तेल के प्रयोग की तकनीकी भी समझाई। साथ ही उद्यानिकी विषय पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से प्रकाशित फल-फूल पत्रिका के अध्ययन की सलाह दी।

पपीता में पोषक तत्व प्रबंधन तथा रोग एवं कीट प्रबंधन की तकनीकी जानकारी देते हुए बताया कि सिंचाई के लिए ड्रीप पद्धति को प्राथमिकता देनी चाहिए जबकि परम्परागत बहाव पद्धति में सिंचाई करने के दौरान वाल का विशेष ध्यान रखे कि सिंचाई का पानी पौधो के तने के सीधे संपर्क में नही आये अन्यथा पपीता में फुट राट नामक बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। प्रशिक्षण के अंत में श्री एसके पर्ते ने सभी प्रशिक्षणार्थियो का आभार व्यक्त किया एवं निमाड़ कृषि समाचार की प्रतियां वितरित की।

## एक गांव एक तालाब'' योजना में जिला प्रदेष में अव्वल

**आगर-मालवा।** मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री राजेष शुक्ल ने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विगत वीड़ियों कांफ्रेंसिंग में उल्लेखित रैकिंग अनुसार जिले में सिंचाई का रकबा बढ़ाने तथा पौधरोपण से पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक गांव एक तालाब योजनान्तर्गत जिले के प्रत्येक ग्राम में नवीन तालाब एवं जीर्णोद्धार के कार्य स्वीकृत कर प्रारम्भ करने में जिला आगर-मालवा प्रदेष में प्रथम स्थान पर रहा। जिले में कुल 515 जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार और 41 नवीन तालाबों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

# म.प्र. को शांति का टापू बनाए रखने में सहयोग दें किसान बाजार का निर्माण करेगी राज्य सरकार

## मंदसौर में जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की आत्मीय चर्चा

**भोपाल।** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मंदसौर जिले सहित प्रदेश के सभी नागरिक मध्यप्रदेश को शांति का टापू बनाए रखने में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का अच्छे से अच्छा दाम मिल सके इसके लिए सरकार किसान बाजार का निर्माण करेगी। इस किसान बाजार में उत्पादक अपनी उपज लाकर बेच सकेगा और अधिकतम मूल्य पा सकेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमने व्यापार उन्नयन बोर्ड का गठन कर दिया है, ताकि प्रदेश में व्यापार व्यवसाय को और अधिक बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि म.प्र. सरकार किसानों से 8रूपये प्रति किलो की दर से प्याज, 5050 रूपये प्रति क्विंटल की दर से तुअर और 5225 रूपये प्रति क्विंटल की दर से मूंग खरीदेगी। हम किसानों को अधिकाधिक नकद भुगतान दिलाने का प्रयास करेंगे।

मंदसौर जिले में बीते सप्ताह हुई घटना का जिक्र करते हुए इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताकर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस घटना से वे बेहद व्यथित हैं, द्रवित हैं, दुखी हैं। वे घटना की जानकारी मिलने की रात चैन से सो नहीं पाये। उन्होंने इस घटना में मृतकों के प्रति अपनी गहन संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस घटना की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच करा रही है। न्यायिक जांच में जो कोई भी इस घटना के लिए दोषी पाया जायेगा, उसको निश्चित तौर पर सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जनता का सेवक हूं और इसी नाते आज आपके बीच मंदसौर आया हूं, ताकि पीड़ितों के बीच जाकर उनकी पीड़ा सुन सकूं और दुख की इस घड़ी में शरीक हो सकूं। उन्होंने क्षेत्रीय नागरिकों से अपील की कि हम सभी अपने प्रदेश की सदियों से चली आ रही शांतिप्रिय संस्कृति के अनुरूप प्रेम व सद्भाव से रहें। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उपद्रव और अराजकता फैलाकर लूटपाट की है, ऐसे अराजक तत्व पहचाने जाएंगे और यकीनन वे किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मंदसौर जिले में हुई घटना में अपने परिजन को खोने वाले परिवारों के बैंक खाते में आरटीजीएस के जरिये एक-एक करोड़ रूपये की सहायता राशि हस्तांतरित कर दी गई है। उनके परिवार में जो भी नौकरी करने योग्य होगा, उसे सरकार नौकरी भी देगी। इसके अलावा जिन नागरिकों/छोटे-बड़े व्यवसायियों के मकान/दुकान, गोदाम, ठेला, गुमटी या अन्य व्यवसायिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, सरकार बेहद उदार हृदय के साथ उनके संपूर्ण नुकसान की समुचित भरपाई करने का प्रयास करेगी। उन्होंने मंडी व्यापारियों से कहा कि किसानों की उपज को सरकारी समर्थन मूल्य पर ही खरीदें, ताकि किसी भी किसान को उसकी उपज का नुकसान न हो।

करीब ढाई घण्टे तक समाज के विभिन्न वर्गो के लोगों से जनसंवाद करने के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान को कुल 45 सुझाव/समस्या/शिकायती आवेदन प्राप्त हुए। सभी की बात विस्तार से सुनने के बाद मुख्यमंत्री श्री चौहान ने एक-एक प्रश्न/समस्या का जवाब दिया और अच्छे सुझावों को सरकार के राजकाज में तत्काल अमल में लाने का आश्वासन भी दिया।

जनसंवाद कार्यक्रम में मंदसौर के लोकसभा सांसद श्री सुधीर गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती प्रियंका डॉ. मुकेशगिरी गोस्वामी, मनासा विधायक श्री कैलाश चावला, मल्हारगढ़ विधायक श्री जगदीश देवड़ा, मंदसौर विधायक श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, नीमच विधायक श्री दिलीपसिंह परिहार, श्री देवीलाल धाकड़, श्री बंशीलाल गुर्जर, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री मदनलाल राठौर, अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, चेम्बर ऑफ कॉमर्स मंदसौर के पदाधिकारी, दशपुर मंडी व्यापारी संघ के पदाधिकारी व अन्य व्यापारी, सर्राफा व किसाना व्यवसायी, विक्रेता, छोटे दुकानदार, किसान, सिंधी समाज के पदाधिकारी, वकील, कुमावत समाज के पदाधिकारी, लोकतंत्र सेनानी संघ के पदाधिकारी, होटल व हलवाई संघ के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक व किसानबन्धु तथा पत्रकार मौजूद थे।

## राज्य मंत्री श्री सारंग द्वारा सुल्तानिया अस्पताल में ब्लड स्टोरेज यूनिट का शुभारंभ

**भोपाल।** सुल्तानिया अस्पताल में जरूरत पड़ने पर ब्लड मिल सकेगा। सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने अस्पताल में ब्लड स्टोरेज यूनिट का लोकार्पण किया। विधायक श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह, डीन जी.एम.सी. डॉ. एम.सी.सोनगरा, अस्पताल अधीक्षक डॉ. किरण पीपरे मौजूद थे।

राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि यूनिट में हर वक्त हर समूह का टेस्टेड ब्लड उपल्ब्ध रहेगा। ब्लड हमीदिया ब्लड बैंक से स्टोरेज में लाकर रखा जायेगा। इससे मरीजों को ब्लड के लिए हमीदिया ब्लड बैंक नहीं जाना होगा। उन्होंने गैस राहत अस्पताल में प्रदेश का आधुनिकतम बड़ा ब्लड बैंक और कमला नेहरू गैस राहत अस्पताल में बोन मेरो ट्रांसप्लांट यूनिट स्थापना के लिए चल रही कार्यवाही के संबंध में भी बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदेश के हर नागरिक तक पहुँचाने की दिशा में किये जा रहे कार्यों की श्रंखला में ब्लड स्टोरेज यूनिट एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि गैस राहत, स्वास्थ्य और श्रम विभाग को ई.एस.आई. आदि द्वारा अलग-अलग स्वास्थ्य सेवाएँ देने के स्थान पर भविष्य में भोपाल नगर में इन सभी विभागों द्वारा परस्पर समन्वय के साथ एक होकर स्वास्थ्य सेवा देने की पहल की जायेगी।

### सर्वोत्तम कृषक पुरूस्कार के आवेदन 15 जुलाई तक आमंत्रित

**भोपाल।** राज्य शासन के निर्देशानुसार वर्ष 2016-17 की गतिविधियों के आधार पर कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम आत्मा के अन्तर्गत पुरस्कार का प्रावधान किया गया है। जिसमें राज्य, जिला, विकास खण्ड के अन्तर्गत कृषकध्समूह को पुरस्कार की सुविधा प्रदान की जायेगी। विभिन्न स्तर जैसे ब्लाक, जिला, राज्य स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार एवं जिला स्तरीय सर्वोत्तम कृषक समुह पुरस्कार प्रदान करने हेतु 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए जायेंगे। विकासखण्ड स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार हेतु कृषि के साथ-साथ उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्यपालन एवं कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषक विभागवार आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, ब्लाक तकनीकी मैनेजर आत्मा अथवा क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकरी से सम्पर्क कर आवेदन प्राप्त कर सकते है।

## मुख्यमंत्री श्री चौहान होंगे टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष

**भोपाल।** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश पर्यटन मंडल की पहली बैठक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। बैठक में मंडल का बैंक खाता खोलने, डिजिटल हस्ताक्षर, भर्ती नियम बनाने, मंडल कार्यालय की स्थापना करने जैसे कार्यों के लिये बोर्ड के प्रबंध संचालक को अधिकृत किया गया। संचालक मंडल में आठ सदस्य होंगे। बैठक में मुख्य सचिव श्री बी. पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव वन श्री दीपक खांडेकर, प्रमुख सचिव संस्कृति श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव नगरीय विकास श्री मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री अशोक बर्णवाल, सचिव मुख्यमंत्री श्री हरिरंजन राव एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

### गौ-अभ्यारण्य सालरिया को मिला नवीन ट्रेक्टर

**आगर-मालवा।** गौ-अभ्यारण्य सालरिया तहसील सुसनेर में पषुधन की देखभाल चारागाह विकास एवं पौधारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शासन स्तर से एक नवीन ट्रेक्टर, ट्रॉली, टैंकर एवं कल्टीवेटर स्वीकृत किया गया है।

## स्वरोजगार में स्थापना हेतु पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग से आवेदन-पत्र आमंत्रित

**गुना।** मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार में स्थापित करने के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए हैं। उन्हें बैंकों से 50 हजार रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

आवेदक की उम्र 18से 55 वर्ष होनी चाहिए तथा उसको गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली सूची में शामिल होना चाहिए। स्वीकृत ऋण पर 30 प्रतिशत मार्जिन मनी सहायता दी जाएगी।

आवेदक को परियोजना, प्रतिवेदन, राशन कार्ड, स्थाई निवास प्रमाण-पत्र, पहचान पत्र, जन्मतिथि संबंधित प्रमाण-पत्र, पिछड़े वर्ग का स्थाई जाति प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड के साथ आवेदन पत्र दो प्रति में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के लिए कार्यालय सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग गुना (कैंची बीड़ी कारखाने के पास केन्ट रोड) से सम्पर्क किया जा सकता है।

## अरहर उत्पादक कृषकों हेतु सलाह

**श्योपुर।** अरहर दलहनी फसलों में खरीफ मौसम की महत्वूर्ण फसल है। इसकी अधिक पैदावार प्राप्त करने की लिए किसान भाइयों को कृषि विभाग द्वारा सलाह दी गई है। जिला सलाहकार एनएफएस कृषि विभाग श्री विशंभर गौड ने बताया कि अरहर की बुआई भूमि में पर्याप्त नमी ( 800-1000 मि.मी. बारिश) होने पर ही करें। अरहर की उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीजों का उपयोग किया जाये। सी.पी.एल.87, आई.सी.पी.एल. 88039, पूसा 992, ट्राम्बे जवाहर तुअर-501,ये सभी किस्मे कम अवधि की है। इसमे लगभग 130 से 150 दिन मे फसल पककर तैयार हो जाती है। इसके अलावा जे.के.एम.-7 एवं जे.के.एम. 189 किस्म के बीजो का उपयोग असिंचित क्षेत्र हैं, जो कि 170 से 190 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। अरहर की बीजोपचार करके वुबाई करें। इसके लिए 2 ग्राम थाइरम1ग्राम कार्बान्डाजिम प्रति किग्रा बीज के मान से बीजोपचार करें। इसके बाद राइजोबियम 5 ग्राम5 ग्राम पी.एस.बी.कल्चर प्रति कि.ग्रा.बीज के मान से कल्चर मिलावें। यदि खेत में खरपतवार की अधिक संमस्या हो तो पेन्डामिथलीन दवा 1.25 ली.को 500-600 ली.पानी में घोलकर वुबाई के बाद एवं बीज अंकुरण से पूर्व खेत में छिडकाव करें।

# किसानों को अपनी उपज सीधे बेचने की सुविधा के लिए प्रदेश में बनेंगे आदर्श किसान बाजार

## किसानों के लिये बनेंगे नॉलेज विलेज सेंटर | बिना किसान की सहमति के नहीं ली जायेगी भूमि

**भोपाल।** किसानों को अपनी उपज सीधे बेचने की सुविधा देने के लिये प्रदेश में आदर्श किसान बाजार बनाये जायेंगे। किसानों तक फसलों के सम्बन्ध में सही और वैज्ञानिक जानकारी पहुँचाने के लिये विलेज नॉलेज सेंटर बनाये जायेंगे। बिना किसान की सहमति के विकास परियोजनाओं की भूमि नहीं ली जा सके, इसके लिये कानून में संशोधन किया जायेगा। ये जानकारी आज यहाँ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गत 11 जून को की गयी किसान हितैषी घोषणाओं की समीक्षा के लिये ली गई बैठक में दी गई। इन घोषणाओं पर क्रियान्वयन भी शुरू हो गया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में निर्देश दिये कि किसानों हित के लिये की गयी घोषणाओं का क्रियान्वयन तेजी से करें। संबंधित आदेश तुरंत जारी करें। सभी मंत्री अपने-अपने विभागों में इनकी समीक्षा करें। एक सप्ताह बाद वे पुनः समीक्षा करेंगे। प्याज खरीदी की व्यवस्थाओं की लगातार मॉनीटरिंग करें।

बताया गया कि सभी नगरीय निकायों और विकासखंड मुख्यालयों में किसान बाजार बनाये जायेंगे। इन बाजारों में किसान खुद फल, सब्जी जैसी अपनी उपजें बेच सकेंगे। नगरीय निकायों में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास विभाग किसान बाजार बनायेंगे। जिन मण्डियों में नीलामी नहीं हो रही है वहाँ पर भी किसान फल, सब्जी जैसी अपनी उपज बेच सकेंगे। इन बाजारों का संचालन सहकारी समिति करेगी। विकासखंड स्तर से ग्राम स्तर तक किसानों को फसलों के संबंध में सही जानकारी और वैज्ञानिक सूचनाएँ पहुँचाने के लिये विलेज नॉलेज सेंटर बनाये जायेंगे। इसकी तैयारी कृषि विभाग द्वारा की जा रही है। इन सेंटरों के माध्यम से किसानों को मौसम की जानकारी, फसलों की संभावनाओं और भूमि के उपयोग के बारे में जानकारी दी जायेगी।

बताया गया कि एक हजार करोड़ के मूल्य स्थिरीकरण कोष की रूपरेखा तैयार कर ली गयी है। इसके आदेश जारी हो गये हैं। इसके माध्यम से जिन उपजों के समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार द्वारा घोषित नहीं किये जाते, उन उपजों का मूल्य निर्धारण किया जायेगा। इस मूल्य से कम मूल्य होने पर किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जायेगी।

कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग के गठन की तैयारियाँ कर ली गयी हैं। इसके माध्यम से फसलों की कृषि लागत तय की जायेगी। यह आयोग छह सदस्यीय रहेगा। इसमें अध्यक्ष के अलावा कृषक, कृषि अर्थशास्त्री और अशासकीय सदस्य होंगे। इसका कार्यकाल दो वर्ष रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसके आदेश तत्काल जारी करने के निर्देश दिये।

जिन फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के आदेश हैं, फेयर एव्हरेज क्वालिटी की ऐसी फसलों की खरीदी समर्थन मूल्य से नीचे नहीं की जायेगी। समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग, तुअर और उड़द की खरीदी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कलेक्टरों को निर्देश दिये गये हैं कि जहाँ आवश्यकता हो अतिरिक्त केन्द्र शुरू किये जायें। किसान आंदोलन के दौरान निजी सम्पत्ति, दुकानों आदि को हुए नुकसान का सर्वे शुरू हो गया है। जिस सम्पत्ति का बीमा नहीं है उसके लिये मुआवजा दिया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सर्वे कार्य तेजी से करने के निर्देश दिये। इसी तरह अमूल डेयरी मॉडल के आधार पर दूध के मूल्य तय किये जाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस मॉडल का विस्तृत अध्ययन करने के निर्देश दिये।

बिना किसान की सहमति के उसकी भूमि विकास परियोजनाओं के लिये नहीं ली जा सकेगी। इस संबंध में कानून में संशोधन करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कृषकों को वर्ष में एक बार खसरा-खतौनी की नकलें निःशुल्क दी जायेंगी। इसके लिये राजस्व विभाग अभियान चलाकर 3 करोड़ 60 लाख खातेदार किसानों को आगामी 15 अगस्त तक निःशुल्क खसरा-खतौनी की नकलें वितरित करेगा। डिफाल्टर किसानों के लिये समाधान योजना बनाई जा रही है जिससे वे दोबारा ऋण लेने के पात्र हो जायें। रबी और खरीफ के लिये एकमुश्त ऋण लेने के संबंध में सहकारिता विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं। किसानों के हित में ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लेने वाला मध्यप्रदेश पहला प्रदेश है। बैठक में मंत्रीगण, मुख्य सचिव तथा सभी संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव उपस्थित थे।

---

### मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना

# बारहवीं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने पर उच्च शिक्षण संस्थान की फीस सरकार देगी

**भोपाल।** अब प्रदेश के प्रतिभावान विद्यार्थियों की 12वीं के बाद भी पढ़ाई की फीस सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ माध्यमिक मण्डल द्वारा करवायी जाने वाली 12वीं परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अथवा सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. की 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा। विद्यार्थी के पालक की आय 6 लाख रुपये से कम होना चाहिए। विद्यार्थी का आधार नम्बर भी जरूरी है।

इंजीनियरिंग-जे.ई.ई. मेन्स परीक्षा में 50 हजार तक की रैंक वाले विद्यार्थियों द्वारा किसी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने पर उसे सहायता मिलेगी। शासकीय कॉलेज की पूरी फीस (मेस शुल्क एवं कॉशन मनी छोड़कर) दी जायेगी। प्रायवेट कॉलेज की फीस में डेढ़ लाख रुपये या वास्तविक शुल्क (शुल्क समिति द्वारा निगमित, मेस शुल्क एवं कॉशन मनी छोड़कर) जो कम हो, शासन द्वारा दी जायेगी।

मेडिकल-राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (नीट) के माध्यम से केन्द्र या राज्य के किसी भी शासकीय मेडिकल कॉलेज अथवा मध्यप्रदेश के किसी प्रायवेट मेडिकल कॉलेज में एम.बी.बी.एस. के लिये प्रवेश लेने पर योजना का लाभ मिलेगा। शासकीय मेडिकल कॉलेज की पूरी फीस एवं प्रायवेट कॉलेज में देय शुल्क राज्य शासन द्वारा दिया जायेगा।

तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी ने बताया कि शासकीय मेडिकल कॉलेज में शिक्षित डाक्टर 2 वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने को बाध्य होंगे। इन्हें 10 लाख रुपये का बांड भरना होगा। प्रायवेट कॉलेज के छात्रों के लिये यह अवधि 5 वर्ष तथा बांड की राशि 25 लाख रुपये होगी।

लॉ- क्लेट के माध्यम से देश के किसी भी राष्ट्रीय विधि विश्व-विद्यालय में बारहवीं कक्षा के बाद के कोर्स की पूरी फीस शासन देगा। राज्य शासन के सभी कॉलेज के बी.एस-सी., बी.ए., बी. काम., नर्सिंग, पॉलीटेक्निक तथा स्नातक स्तर के सभी पाठ्यक्रमों की पूरी फीस सरकार भरेगी।

# प्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनाने राज्य सरकार और कदम उठायेगी

**वित्त मंत्री श्री मलैया ने किसानों को बीज मिनिकिट वितरित किये**

**भोपाल।** वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने कहा है कि प्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिये राज्य सरकार और कदम उठायेगी। राज्य में खेती के विकास के लिये लगातार काम किये जा रहे हैं। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है। दमोह की सिंचाई की महत्वाकांक्षी सतधरू योजना से 25 हजार एकड़ क्षेत्र में सिचाई होगी। योजना के लिये 315 करोड़ रुपये और मंजूर किये गये हैं। वित्त मंत्री श्री मलैया कृषि विज्ञान केन्द्र दमोह में किसानों को बीज मिनिकिट वितरण करने के बाद किसानों को संबोधित कर रहे थे।

वित्त मंत्री श्री मलैया ने कहा कि किसानों को खेती के लिये 10 घंटे बिजली दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक प्रदेश में प्रत्येक आवासहीन को आवास बनाकर दिये जायेंगे। इसके लिये जिले में तेजी से काम किया जा रहा है।

## 40 प्रतिशत राशि जमा करने पर पूरी छूट मिलेगी

**भोपाल।** राज्य शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा मध्य प्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश जारी किया गया हैं। सरल समाधान योजना लागू बकाया कर, पेनाल्टी व ब्याज की राशि पर 40 प्रतिशत राशि जमा करने पर पूरी छूट मिलेगी।

आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप एक में आवेदन-पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष 27 जुलाई तक प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ समाधान राशि जमा करने का प्रमाण संलग्न करना होगा। बकाया में एक निश्चित राशि जमा करने पर विभाग द्वारा राशि माफ की जायेगी। इस योजना में केवल विक्रय कर, वाणिज्यिक कर, वेट एवं केन्द्रीय विक्रय कर की बकाया के समाधान हेतु आवेदन किया जा सकता हैं, ताकि उक्त योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकें।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा सांध्य प्रकाश लि.'सांध्यप्रकाश भवन' मालवीय नगर, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।